बुनियादी मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती ?

पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बच्चे अस्पतालों में मर रहे हैं, हम हिंदू-मुसलमान में उलझे हैं

-रवीश कुमार

हिन्दू मुस्लिम टापिक से दिल भर गया हो क्या कुछ समय के लिए हम स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के सवाल पर बात कर सकते हैं। उससे पहले हम अर्थशास्त्र से जुड़ा एक सवाल कर सकते हैं कि दुनिया के हर अर्थशास्त्री ने समझाया कि तेल के दाम बढ़ने से बाकी चीजों के दाम बढ़ते हैं. क्या अब ये थ्योरी पलट गई है, तेल के दाम बढ़ने से बाकी चीजें सस्ती हो जाती हैं, उनका कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता। इंडियन आयल की वेबसाइट पर प्रोडक्ट प्राइसेस नाम के कालम में पेट्रोल और डीजल के दाम मिलेंगे. सोमवार को अलग अलग शहरों के दाम इस तरह हैं-

मुंबई में 79.41 पैसा प्रति लीटर
भोपाल में 76.70 प्रति लीटर
पटना में 74 रुपया 63 पैसा प्रति लीटर
कोलकाता में 73.05 प्रति लीटर
लखनऊ में 72 रुपया 43 पैसा प्रति लीटर
दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपये 30 पैसा प्रति लीटर

देश की 18 राजधानियों में पेट्रोल का दाम सत्तर के क्लब में भर्ती हो गया है। कभी 60 रुपये प्रति लीटर होने पर हंगामा होता था, अब 70 रुपये पर भी चुप्पी है। लोगों की आर्थिक क्षमता इतनी बढ़ गई है, कम से कम इसी पर बात हो सकती थी। एक थ्योरी और कहीं घास चरने चली गई है। पहले कहा जाता था कि दुनिया के बाजार में क्रूड आयल कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो भारत के शहरों में पेट्रोल महंगा हो जाता है। अब तो क्रुड़ आयल का दाम कब का दम तोड़ चुका है. फिर भी पेट्रोल का दाम बढ़ता ही जा रहा है।

तभी कहता हूं कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा न हो इसके लिए सबसे अच्छा टापिक है हिन्दू मुस्लिम। कोई भी ऐसा विषय हो जिसकी बहस दो समुदायों के बीच दुराव पैदा करती है ऐसी बहसों से मीडिया का स्पेस भरा हुआ है। वर्ना आप इस बात से सिहर उठते कि आखिर क्या बात है कि शहर दर शहर, अस्पताल। इन मौतों को आप सरकारों की पार्टी के हिसाब से मत देखिये। इस हिसाब से देखिये कि जमाने से स्वास्थ्य व्यवस्था की जो उपेक्षा की गई है, वो अब खुद से सतह पर आने लगी है।

...बच्चों की मौतों पर नहीं पसीजता दिल

गोरखपुर तो कब का पीछे छूट गया है। जमशेदपुर, रांची, फर्रूखाबाद, इटावा होते हुए नासिक पहुंच गया है। नेताओं के भाषणों को गौर से सुनिये आपको किसी भी भाषण में बच्चों की हो रही मौत या जर्जर हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेचैनी नजर नहीं आएगी। आप उनसे कहेंगे कि अस्पताल में डाक्टर क्यों नहीं हैं, दवा क्यों नहीं है तो उसके जवाब में कहेंगे कि स्वास्थ्य बीमा तो है ही। बीमा से डाक्टर का काम हो जाता तो मेडिकल कालेज की जगह इस देश में बीमा के कालेज खुल रहे होते। बुनियादी सवालों पर नकली बहसों के जरिये चाहे जितना ही पर्दा डालने की कोशिश हो, जनता की तकलीफ समंदर के किनारे आ ही जाएगी।

नासिक के अस्पताल में एक भी स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं था। बच्चों की मौत के अलग अलग कारण हो सकते हैं, मगर क्या इसके भी अलग अलग कारण हैं कि एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है बच्चों के इलाज के लिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत

भी मानते हैं कि मरीजों का दबाव बढ़ गया है। पर क्या दीपक सावंत इसका समाधान कर सकते हैं, उनके पास बजट है, एक अस्पताल के लिए है या सभी अस्पतालों के लिए है, यह समस्या तो महाराष्ट्र की नहीं, करीब करीब हर राज्य की होती जा रही है।

बुलेट ट्रेन आ रही है लेकिन गुजरात में 58 फीसदी सरकारी डॉक्टरों की कमी है

2 सितंबर को गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि गुजरात के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की पोस्ट खाली क्यों है। याचिकाकर्ता मनस्वी थापर ने दावा किया है कि विशेषज्ञ डाक्टरों के 942 पदों में से 649 पद खाली हैं। 58 फीसदी पद खाली हैं तो इलाज कौन कर रहा है, नेताजी का भाषण? यही नहीं राज्य में जनरल फिजिशियन के 1200 से अधिक पोस्ट खाली है। याचिकाकर्ता के वकील के आर कोष्ठी ने दलील दी कि सरकारी अस्पतालों में डाक्टर न होने के कारण मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। स्वाइन फ्लू के मामले में के आर कोष्ठी ने कहा कि गुजरात के 24 जिलों के सरकारी अस्पतालों में स्वाईन फ्लू की जांच के लिए लेबोरेटरी ही नहीं है। इस बीमारी की चर्चा 2009 से भारत में हो रही है अगर गुजरात जैसे विकसित राज्य के अस्पतालों में लैब नहीं है तो बाकी देश का क्या हाल होगा। गुजरात सरकार ने इसी केस में अपने जवाब में कहा है कि राज्य में 1407 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें 1784. मेडिकल अफसर तैनात हैं. कायदे से मेडिकल अफसर एम बी बी एस ही होता है लेकिन इस सूची में 76 वन बंधु और 732 आयुष के चिकित्सकों को भी मेडिकल अफसर में गिना गया है। इस आंकड़े के हिसाब से भी 55 जगहों पर मेडिकल अफसर नहीं है।

2015-16 में गुजरात पर सी ए जी की रिपोर्ट आई थी जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण की योजनाओं का आडिट किया गया है। सीएजी ने कहा है कि सरकार ने इन योजनाओं पर खर्च होने वाले पैसे में 2014-15 के मुकाबले, 2015-16 में 11 प्रतिशत की कमी की है। एक साल में 11 प्रतिशत की कटौती बहुत होती है।

घाना से भी बदतर हैं असम व मध्य प्रदेश की सेहत के हालात

वेबसाइट पर 16 अगस्त को चैतन्य मल्लापुर ने एक विश्लेषण किया है।

भारत में पांच साल से कम के दो बच्चे हर मिनट मर जाते हैं।

2015 के साल में हर दिन 2,959 बच्चों की मौत हुई है।

2015 में 1000 में से 43 बच्चे पांच साल से उम्र पूरी करने से पहले ही दम तोड़ गए।

असम और मध्यप्रदेश का रिकार्ड तो अफ्रीका के घाना से भी बदतर था।

पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का प्रतिशत ज्यादा होता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। सेव दि चिल्ड्रेन नाम की संस्था के अनुसार 90 प्रतिशत मामलों में न्यूमोनिया और डायरिया से मौत हो जाती है जिसे आसानी से टाला जा सकता था। सरकार ने कई कार्यक्रम बनाए हैं मगर फिर भी खास सुधार नहीं है।

तहसील परिसर के बाहर सरकारी दवाइयों से भरा गत्ता क्रूड के ढेर में मिलता है। हमारे सहयोगी अरशद जमाल ने इटावा से भेजी है। सैफई महोत्सव वाले सैफई में एक महीने में 96 बच्चे कुपोषण से मर गए। ये जो दवाएं हैं वो कुपोषण से लड़ने के लिए ही हैं। ये आयरन और फालिक एसिड की दवाएं हैं जिन पर एक्सपाइरी डेट भी दिसंबर 2018 की है। इन दवाओं को गर्भवती महिलाओं को निशुल्क दिया जाना था। ऐसी कई कहानियां टीवी को रोज मिल सकती हैं बस उसे कोई हिन्दू मुस्लिम टापिक से उसे आजाद कर दे।

सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट पिछली सरकार में 90 करोड़ बताया जाता था, जो अब 30 करोड़ का हो गया है। बच्चों के लिए साठ बेड हैं। मगर हर महीने यहां 1200 से 1500 बच्चे एडमिट होते हैं। पिडाट्रिक (बच्चों का) विभाग का बजट आर्थोपेडिक (हड्डियों का) विभाग में हो जाने की बात सामने आई है। यहां 8 जिलों से लोग इलाज के लिए आते हैं। आठ आठ जिलों में एक अस्पताल है। फिर भी जनता को भी देखिये हिन्दू मुस्लिम टापिक में मस्त है।

(एनडीटीवी में कार्यरत रवीश कुमार जाने-माने पत्रकार हैं)

किसानों को कर्जमाफी के नाम पर बेइज्जत कर रही योगी सरकार

अखबारों में छप रहे कर्जदार किसानों की सूची देखकर किसान हैं आहत, खफा हैं इस बात से कि करोड़ों के डिफॉल्टर पूंजीपतियों का नाम छापने की बारी आने पर सरकार की हेकड़ी निकल आती है और गरीब किसानों को बेइज्जत करके मुख्यमंत्री दांत निपोरते हैं...

लखनऊ। सरकार की हिम्मत नहीं कि वह अरबों की रकम डकार चुके पूंजीपतियों का नाम सार्वजनिक करे, लेकिन यहां 9 पैसे वाले किसानों का नाम गर्व से सरकार अखबारों में छपवाकर किसान हितैषी बनने का नाटक कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहला वादा किया था, वह था किसानों की कर्जमाफी। लेकिन अब जब कर्जमाफी का मौका आया है तो सरकार कर्जमाफी के नाम न सिर्फ किसानों का मजाक उड़ा रही है, सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत भी कर रही है।

मीडिया और सोशल मीडिया में कर्जमाफी वाले किसानों की जो सूची छप रही है, उससे साफ है कि सरकार कर्जमाफी की गिनती बढ़ाने के लिए किसानों के साथ यहअसंवेनशील कारगुजारी यूपी सरकार कर रही है।

कर्जमाफी की खबरें और किसानों का मजाक उड़ाती कर्जराशि की सूचियां हर रोज किसी न किसी स्थानीय अखबार में छप रही हैं। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता यह है कि वह खुद 73 या 75 रुपए कि कर्जमाफी का प्रमाणपत्र मंचों से किसानों को प्रदान कर रहे हैं।

बाराबंकी जिले के किसान रामनरेश पटेल कहते हैं, ''ये कोई कर्जमाफी है। कल को हम बेटे—बेटियों की शादी करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये देखो इनका तो कर्जदार के नाम पर अखबारों में नाम

छपा था। किसानों के इस मजाक की कीमत योगी और मोदी 2019 में चुकाने के लिए तैयार रहें ''

किसान नेता और योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुधीर पंवार कहते हैं, शायद यह पहली बार हो रहा है कि किसानो की ऋण माफी में किसान को स्टेज पर बुलाकर यह महसूस कराया जा रहा है कि देखो तुम कितने नाकारा और ग़रीब हो और अमुक पार्टी के मंत्री जी कितने दयालु कि तुम्हारा क़र्ज़ा माफ़ कर रहे हैं।

किसान नेता पंवार नागरिक अधिकार संगठनों से अपील करते हुए कहते हैं, सरकार ने अभी तक बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए है और न ही काला धन रखने वालों के। एक देश मे दो व्यवस्था कैसे हो सकती है। एक ओर करोड़ों के क़र्ज़दार उद्योगपति का नाम गुप्त रखा जाता है और दूसरी ओर दस—बीस रुपए से लेकर 9 पैसे के कर्जदार किसानों के नाम स्टेज पर बुलाकर सबके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। यह बुनियादी तौर पर किसानों के मान को ठेस पहुंचाना और सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना है। नरेश कुमार सिंह दिल्ली की एक कंपनी में मैनेजर हैं। वह सहारनपुर जिले की एक तहसील के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम अखबार में 97 रुपए की कर्जमाफी के लिए अखबार में छपा है। उनके गांव और परिवार के वाट्सएप ग्रुप में उनके पिता वाली सूची घूम रही है और लोग एक—दूसरे को भेज रहे हैं।' नरेश कहते हैं, मैं किसी वकील से संपर्क सरकार की इस कारगुजारी के खिलाफ मुकदमा करना चाहता हूं। कर्ज जैसा कर्ज नहीं और बेइज्जती पूरी।' बुंदेलखंड में किसानों के मसलों को लेकर सक्रिय रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर दीक्षित हमीरपुर के एक किसान के कर्जमाफी का प्रमाण पत्र लगाते हुए योगी सरकार से पूछते हैं, इस किसान का 10 रुपया 37 पैसा कर्जा माफ हुआ है। यह है योगी की कर्जमाफी ? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को।

आशीष सागर दीक्षित द्वारा दिखाए जा रहे प्रमाण पत्र के कंफरमेशन के लिए जनज्वार ने नीचे दिए गए नंबर पर फोन किया तो पता चला कि यह नंबर कंट्रोल रूम प्रभारी हमीरपुर का है। जिस व्यक्ति ने फोन उठाया उसने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर कंट्रोल रूम जिला प्रभारी है। प्रदेश भर में राज्य सरकार ने किसानों के सवालों को हल करने के लिए कंट्रोल रूम बना रखे हैं। 10 रुपया 37 पैसे की कर्जमाफी पर अधिकारी ने बड़े गर्व से बताया, जितना कर्जा होगा उतना ही माफ होगा न।

न्यायिक इत्तफाक या न्याय खाक में

– राना अयूब ने अपनी पहचान छिपाकर गुजरात नरसंहार के पीछे की कहानी से पर्दा हटाया और उसे एक किताब की शक्ल दी। उनकी किताब 'गुजरात पेपर्स' दो वर्ष पहले अंग्रेजी में आई लेकिन मीडिया ने उसके अस्तित्व से ही मुंह मोड़ लिया। इसी सोलह सितम्बर को दिल्ली प्रैस क्लब में किताब के हिन्दी संस्करण का विमोचन किया जाना था, जिसे भी मुख्य धारा मीडिया ने नजरअन्दाज किया।

– कन्हैया कुमार को देशद्रोह के नारे लगाने के जुर्म में गिरफतार किया गया और जमकर उनकी फजीहत की गई। सिद्ध यह हुआ कि उन्होंने कोई नारा लगाया ही नहीं था, उन पर केस तब भी चल रहा है।

– सुप्रीम कोर्ट में जिस न्यायाधीश ने अमित शाह को हत्या, अपहरण ठगी आदि केस से बरी कर दिया था वह जज रिटायर के 7 दिन बाद केरल के राज्यपाल बन गए।

– जो वकील अमित शाह का केस लड़ रहा था वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज बन गये हैं...

– गुजरात हाई कोर्ट में जो जज अमित शाह को अभियुक्त करार देते हुए दंडित किया उनके बहन की शादी में आय कर विभाग का छापा पड़ा।

–